of Andhra Pradesh State Electricity Board for installation of two units of 500 MW each at Vishakhapatnam at an estimated cost of Rs. 1560.28 Crores was techno-economically cleared by the Central Electricity Authority on the 23rd October, 1990, subject to the confirmation of water availablity from the State Irrigation Department as well as the Central Water Commission and. the submission of Ely Ash Utilisation Management Plan by the APSEB. The water availability for the Project has since been confirmed by the Irrigation Department of Andhra Pradesh but the clearance of the CWC is still awaited. The plan for fly ash utilisation has been received from APSEB on which certain clarification have been sought from APSEB by the Central Electricity Authority.

The Project Report submitted by NTPC in December '87, tor Manuguru STPS, 2x500 MW, at an estimated cost of Rs. 1129.60 Crores under Central Sector is under examination of the CEA. The Project could be considered for techno-economic clearance of the CEA after all the inputs/clearances such as Coal linkage, E&P clearance and Associated Transmission System etc are tied up.

आठवीं योजना के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को कम करना

81. **श्री राम जेठमलानी** : क्या विद्युत और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के लिए बिजली उत्पादन के पूर्व-निर्धारित लक्ष्य को कम करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस सम्बन्ध में किये गये पूर्व-निर्णय की पुनरीक्षा करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने विगत में इस सम्बन्ध में कोई सुधारात्मक उपाय किये हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के लिए विद्युत उत्पादन के लक्ष्य को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का कार्यकरण

82. **श्री राम जेठमलानी** :
सरदार जगजीत सिंह अरोडा :

क्या विद्युत और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 जून, 1991 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "डेमू ब्लेमड फोर लोड शैडिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कार्यकरण के सम्बन्ध में नियुक्त समिति ने अपने विस्तृत प्रतिवेदन में किन-किन कमियों का उल्लेख किया है ;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी कमियों की पुनरावृत्ति न होने देने के सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाए हैं ;

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) ऐसा प्रतीत होता है कि कथित समाचार, दिल्ली में विद्युत सप्लाई की स्थिति और इसमें सुधार हेतु किए जाने वाले उपायों की आवधिक रूप से समीक्षा हेतु सरकार द्वारा गठित कृतिक बल के टीका-टिप्पणी पर